'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.08.2015
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: aicscst@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 18 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 अगस्त, 2015

अनुसूचित जाति-जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) संशोधन बिल, २०१४ पास करने के लिए प्रधानमंत्री एवं सरकार को धन्यवाद

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2015.

गत् कई वर्षों से अनुसूचित जातिध्जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से मांग करता आ रहा रहा हूं कि 'अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989' में तमाम कमियों की वजह से अक्सर दोषी छूट जाते हैं। अब तक जो मामले इस ऐक्ट के तहत दर्ज किए जाते थे, उनमें सिर्फ 2 से 8 प्रतिशत लोगों को ही सजा हो पाती थी लेकिन आज लोक सभा ने जब 'अनुसूचित जातिध्जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) संशोधन बिल, 2014' पास किया तो यह एक मजबूत अधिनियम बन गया है और दोषियों का बच पाना अब मुश्किल हो जाएगा। किसी भी दलित को चुनाव के समय किसी प्रत्याशी को वोट डालने हेतु दबाव देना, उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे, उनके साथ अभद्रता, आदमी अथवा जानवर का मैला सिर पर ढोना, आदि के विरूद्ध भी इस अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जा सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल से रोकना, जादू टोने के आरोप लगाना, धार्मिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना और बैर–भाव को बढ़ावा देने जैसे अपराधों के खिलाफ मुकदमे चलाने के लिए विशेष अदालतें गठित करने और पीड़ितों के पुनर्वास का भी प्रावधान है। अब शिकायतकर्त्ता को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसके साथ अन्याय हुआ है, बल्कि उत्पीड़क को सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने अपराध नहीं किया है।

अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) संशोधन बिल, 2014 पास करने के लिए प्रधानमंत्री एवं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं।

– (उदित राज)
सांसद, लोक सभा

✦✦✦

लखनऊ में परिसंघ का सम्मेलन संपन्न

अनुसूचित जाति /जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय समन्वयक एवं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, दि. बुद्धिष्ट सोसाइटी ऑफ इण्डिया, अखिल भारत अनुसूचित जाति परिष के प्रदेश अध्यक्ष तथा ऑल इण्डिया सेन्ट्रल वेअरहाऊसिंग कार्पोरेशन अनुसूचित जाति/जन जाति एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगजीवन प्रसाद जी का केन्द्रीय भण्डारण निगम,लखनऊ में सहायक वास्तुविद की सरकारी सेवा से दिनांक 31 जुलाई, 2015 को सेवा निवृत्त होने के बाद अपने आवास 61, अर्जुनगंज, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में 2 अगस्त, 2015 रविवार को परिसंघ के चेयरमैन तथा दिल्ली से निर्वाचित लोक सभा सदस्य डॉ. उदित राज का स्वागत एवं अभिन्दन किया।

श्री जगजीवन प्रसाद जी के विदाई एवं स्वागत का कार्यक्रम अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की विगत 19 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली के मावालंकर सभागार में आयोजित राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के पूरे भारत से आये परिसंघ के नेताओं के दलित अधिकार चिंतन बैठक से शुरु हुआ जिसमें परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री ब्रह्मप्रकाश जी के प्रस्ताव पर सम्मेलन में आये सभी 600–700 सौ लोगों को जगजीवन प्रसाद जी के द्वारा अपनी ओर से दिये गये लन्च (भोज) से शुरु हुआ। उसके बाद उन्हें केन्द्रीय भण्डारण निगम, लखनऊ जहाँ से वे 31 जुलाई, 2015 को अपनी सरकारी सेवा के अन्तिम दिन उन्हें विभागीय अधिकारियों– कर्मचारियों तथा विभागीय नेताओं द्वारा विदाई पार्टी दी गई, सबसे पहले ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ सी.डब्लू.सी इम्पलाइज युनियन्स के प्रमुख श्री डी. एल. चण्डोक द्वारा जगजीवन प्रसाद जी के सम्मान में उन्हें शाल भेट कर फूल–मालाओं से स्वागत किया तथा सभी लोगों को मिठाई–नमकीन खिलाते हुए उनके विभागीय कार्यो तथा अधिकारी वर्ग में आने से पहले ट्रेड युनियन में किए गये सामाजिक एवं कर्मचारी हितो के लिए कार्यो की प्रशंशा की गई और विशेष बात यह रहीं कि श्री चण्डोक साहब अपने कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ दिल्ली से चलकर लखनऊ मात्र श्री जगजीवन प्रसाद जी को विदाई एवं सम्मान देने के लिए एक दिन पहले ही पहुँच गये थे, और इस मौके पर सभी विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।

दोपहर के बाद लगभग 3 बजे से मुख्य फेयरवेल पार्टी का आयोजन शुरु हुआ उस दिन जगजीवन प्रसाद जी सहित अधिकारी ऐसोसिएशन के क्षेत्रीय सचिव उत्तर प्रदेश श्री बालाजी चतुर्वेदी जी, जयप्रकाश जी एवं विजय शंकर गुप्ता की भी विदाई समारोह पार्टी थी। पहले ट्रेड युनियन के नेताओं का विदाई

For the fist time SC/ST welfare association has been raised Dr. Udit Raj Congratulates the Govt. and PM for passing Atrocities Bill

New Delhi, August 4, 2015.

I would like to congratulate the Narendra Modi led NDA Government for passing the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2014 in the Lok Sabha today. I am also thankful that the Government took the route of an Ordinance in 2014 till the time such a Bill could be passed by Parliament. The Bill, as was introduced in the Lok Sabha in 2014, seeks to ensure further protection of rights of SC/ST sections of society and ensure that the definition of atrocities under the Act extends to either forcing an SC/ST voter to vote or not vote for a particular candidate, wrongful occupation of their lands and instances of assault or sexual exploitation. New offences, which have predominantly been facets of caste-based violence, such as garlanding with footwear, compelling to dispose or carry human or animal carcasses, or do manual scavenging, or imposing or threatening a social or economic boycott have been included in the Bill. It is also worth pointing out here that the conviction rate under the earlier Act was abysmally low at around 2 to 8%, as the onus of proof was on the victim, which has now been changed in the Act to place the burden of proof on the perpetrator. In this regard, it is also a good move to ensure that an Exclusive Special Court and Special Public Prosecutors be appointed at the District level to try cases under the new Act.

I have been at the forefront of the movement to bring about these changes in the Act, to ensure justice to victims and more importantly, to ensure that perpetrators do not make use of loopholes in the law to escape scot free. It is deeply gratifying that the Bill for which I have been working for the last 18 years, both within Parliament and outside amongst the masses via the All India Confederation of SC/ST Organizations, of which I am the founder Chairman has been passed today.

- (Udit Raj) Member of Parliament, Lok Sabha

शेष पृष्ठ 4 पर

संघर्ष का पैमाना

अमरनाथ ने दलित विमर्श की सीमाए(12 जुलाई) में लिखा है कि दलित साहित्य भटकाव का शिकार तो है ही, वह अमीरी-गरीबी की खाई को और बढ़ाने में अनजाने ही मद्द पहुंचा रहा है। समाज के चिंतकों का ध्याान वर्ग-संघर्ष की हकीकत से हट कर दलित-विमर्श और स्त्री-विमर्श की भूलभुलैया में भटक गया है, जबकि जाति-पांति और छुआछूत एक मरणासन्न सामंती मूल्य है और वर्ग-संघर्ष एक जिंदा हकीकत।

यह सच में भटकाव है या भूलभुलैया, जिससे निकल पाना सहज नहीं! ठस सहजता का प्रेरणास्त्रोत जिसे बंगाल भूमि को बताया गया है वह भी समीचीन नहीं लगता। यह सही है कि सबसे पहले जाति-व्यवस्था का बहिष्कार यहीं हुआ। नवजागरण के सभी महापुरुष, जो सवर्ण कुल के थे, इसके पुरोधा बने। जाति-पांति, छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई। सामाजिक स्तर पर उसका प्रभाव अंतर्जातीय वैवाहिक संबंध के रूप में उपजा, जो अन्य राज्यों में इस तहत संभव नहीं है। हरियाणा की खाप पंचायतों को चलना इसका प्रमाण है। स्त्री शिक्षा के लिए भी जितने कार्य नवजागरण काल में हुए उसके चलते सचमुच बंगाल उदाहरण बनने के लायक है। महिला सशक्तीकरण का सुवास बंगाल भूमि से ही सर्वत्र फैला।

पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जहां जाति-व्यवस्था की जड़ें एक महीन आवरण में सांस लेती आई है और शायद भविष्य में भी कमोबेश यही स्थिति रहने वाली है। आपको अचरज होगा कि आजादी के अड़सठ वर्षो बाद भी कोई दलित बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं बना। पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति भी सत्ता में अपना दबदबा नहीं बना पाया। बंगाल में शुरु से लेकर आज तक ब्राह्मण और क्षत्रिय ही सत्ता पर काबिज रहे। पार्टी बदली, लोग बदले, पर दबदबा सिर्फ दो जातियों का रहा। इसका क्या अर्थ समझा जाए ?

सत्तर के दशक में मुख्यमंत्री प्रफुल्लचंद्र सेन ने एक सभा में कहा था मैं स्वयं क्षत्रिय हूं फिर भी यह कहने के लिए बाध्य हूं कि जाति-व्यवस्था के दंश से मुक्ति दिलाने में आग्रणी इस बंगाल भूमि पर होना चाहिए। इसके विपरीत, भारत के अन्य राज्यों में उदाहरण के तौर पर देखें तो बिहार में कई जातियां सत्ता में आई है। ब्राह्मण, क्षत्रियों से कही ज्यादा वैश्यों और शूद्रों का शासन चला है। अमरनाथजी की बात सही है कि आज बंगाल की दशा यह है कि यहां जाति के आधार पर टिकट लेने और वोट मांगने वालों की जमानत जब्त हो जाएगी। पर परोक्ष रूप में जो हकीकत है उस पर क्या टिप्पणी की जाए! जति के प्रति तो कोई आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि बड़ी चालाकी से जनता को दूसरे मुद्दों में उलझाा दिया जाता है। वर्ग संघर्ष के तौर पर अमीर-गरीब का संघर्ष तो है ही। बंगाल के गांवों में जमींदारों के सताए हुए लोग मजदूर बन गए। जाति का कोहराम इस मजदूरी का सोमरस बना, जिसे वे आज तक पीते आ रहे है। कोलकता को ही देखें तो कई राज परिवार आज भी उसी ठाठ से जी रहे है। राजबाड़ी का रूतबा कायम है, पर मजदूर बना कर रखने की परिपाटी में थोड़ी कमी जरूर आई है।

वर्ग-संघर्ष के कई और रूप हैं। वृद्ध और युवा वर्ग का संघर्ष कम से कम राजनीति में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। सारे मुख्यमंत्री पचास वर्ष से ज्यादा उम्र के रहे हैं। नई पीढ़ी को यह कह कर मौका नही दिया जाता कि शासन अनुभवी व्यक्ति ही चला सकता है। वहां एक अन्य किस्म का वर्ग-संघर्ष है, जो आखिरकार 2011 में पहली महिला मुख्यमंत्री बनने पर खत्म हुआ। इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अगर बंगाल में स्त्री शक्ति को अरसे से सम्मान मिलता रहा है, तो उस मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई। गौरतलब है कि 2011 में पहली महिला मुख्यमंत्री भी महिला सशक्तीकरण के बजाय वाम सरकार के कुशासन के विरोध में बनी! शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर डॉक्टरी या इंजीनियरिंग जैसे पेशों में ब्राह्मण, क्षत्रियों की लंबी कतार नजर आएगी। किसी भी शहर या इलाके के डॉक्टरों की सूची तैयार करके देख लें हकीकत से दो-चार हो जाएंगे। हां, अब स्थिति बदल रही है। हर कुल का बच्चा इन पेशों को अपनाने की कोशिश कर रहा है और सफल भी हो रहा है। पर इससे भविष्य कितना बदलेगा यह तो समय बताएगा।

थोड़ी और गहराई में जाएं तो बंगाल में जाति-संघर्ष और वर्ग-संघर्ष के अलावा भाषाई संघर्ष विकराल रहा है। पड़ोसी राज्यों से लोगों ने रोजगार की तलाश में बंगाल में कदम रखा। आबो-हवा पसंद आ गई, सुख-सुविधा रास आ गई तो धीरे-धीरे वहीं बसने लगे। परिणाम भाषाई संघर्ष के रूप में सामने आया। धड़ल्ले से उपनाम दिए जाने लगे। बिहार से आने वालों को भेइों ओड़िशा वालों को उड़ों, मुसलमानों को नेड़ो, दक्षिण भारतीयों को तेतूल, पंजाबियों को पइयां जैसे हिकारत भरे उपनाम से संबोधित कर अपना रोष निकाला गया। आज भी वह हिकारत खत्म नहीं हुई है।

बंगाल के बाहर भी भाषाई संघर्ष है, पर इसकी शुरुआत का श्रेय बंगाल को अधिक है। आखिरकार पहले-पहल अंग्रेजी सत्ता के चलते बंगाल में अन्य राज्यों के लोगें आए और उसे संवारने में अपनी भूमिका निभा गए। औघोगिक क्षेत्र में बंगाल की ऊंची जातियों ने अपना दबदबा कायम रखा। इसके चलते कोई दलित उस तरह अपनी पैठ नहीं बना पाया। तमाम उद्योग-धंधों के मालिक ऊंची जाति के है, क्योंकि सुविधाओं के स्त्रोतों पर उनका ही कब्जा रहा है। समय गुजरता गया और छोटी जातियों को पैर रखने की जगह नहीं दी गई और न संघर्ष करके वे रख पाए।

अब जरा साहित्य जगत में इस संघर्ष की पड़ताल। तमाम बड़े साहित्यकारों में वंद्योपाध्याय, चट्टोपाध्याय, उपाध्याय, बनर्जी, मुखर्जी, सेनगुप्ता, राय की लंबी कतार है। इसमें दलित साहित्यकारों दुराव का संघर्ष भी कायम है। बांग्ला साहित्य का हिंदी में भरपूर अनुवाद होता है, लेकिन प्रेमचंद के अलावा बहुत कम साहित्याकारों की रचनाओं का अनुवाद बांग्ला में हुआ है। अनुवाद क्रम में बंगाल भूमि से संबंध जोड़ कर देखना भी एक कसौटी रहा है। निराला के साहित्य का अनुवाद इसका प्रमाण है। ऐसे में बांग्ला साहित्य की परिधि संकीर्ण हो गई हैं, जिसमें विस्तार के लिए संघर्ष होना तय है । संक्षेप में, संघर्ष का पैमाना बड़ा है और बढ़ा भी है। दलित साहित्य लेखन के बजाय समाज की ज्वलंत समस्याओं के लिए संघर्ष होना आवश्यक है।

दै. जनसत्ता (19 जुलाई, 2015) से साभार

+++

स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर व्याख्यान सम्पन्न

पूर्व की परम्परा में हुयी चूक, नतीजा हमारे सामने

मुगलसराय उत्तर प्रदेश जीटी रोड नई बस्ती स्थित अग्रवाल सेवा संस्थान में स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत चंदौली के तत्वावधान में शनिवार को एक व्याख्यान सम्पन्न हुआ जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद एवं दलित नेता डॉ. उदित राज थे।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को दिया। इसे भाजपा का नहीं बल्कि देश का कार्यक्रम माना जाये। वास्तव में इस देश में स्वच्छता की कमी है। अस्वस्थ वातावरण में रहने के कारण प्रत्येक भारतीय को 6,500 रुपये बीमारी पर खर्च करना पड़ता है। लगभग एक वर्ष होने वाला है लेकिन अभी भी इस ऐलान का असर कम दिखाई पड़ता है। हमें कारणों की तलाश करनी होगी जो हमें स्वस्थ होने से रोकता है। अपने घर की गंदगी को सड़क पर फेंकने में कोई झिझक नहीं होती। डॉ. उदित राज ने कहा कि दरअसल कुछ कमियां हमारे खून में घुस गयी हैं। मसलन गन्दा करने वालों को हम ऊंच और गन्दगी साफ करने वालों को हमने नीच मान लिया। पेशे को जब हमने ऊंचाई और नीचाई से जोड़ना शुरु किया तो हमारी मानसिकता भी वैसी ही बन गयी। हमने यह मान लिया कि साफ सफाई करना हमारा काम नहीं हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है। वे गन्दगी के प्रति अधिक जागरुक हैं। गोष्ठियों की मदद से धारणाओं को बदलना होगा। हाथ से काम करने वाले को हम नीच न समझें। इस तरह की धारणा बनने पर ही समाज में परिवर्तन आ सकता है।

डॉ. उदित राज ने संकेत कीया कि प्रत्येक छोटे काम को सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए। गांधी जी के भक्त तो बहुतेरे हैं लेकिन वो भी अपनी गन्दगी की सफाई स्वयं नहीं करते। इतना ही नहीं सफाई करने वालों को इज्जत भी नहीं देते। यह गलती हजारों वर्ष से होती चलती आ रही है जिसका परिणाम यह निकला कि सारा कामकाज छोड़कर सरकार को गन्दगी की तरफ फोकस करना पड़ा। गन्दगी साफ करना इज्जत का काम है, जब तक यह भावना जागृत नहीं होगी तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। हमने अपनी शिक्षा प्रणाली में सफाई को एक विषय के रुप में कभी नहीं लिया। देश के सैकड़ो सौ विश्वविद्यालय, हजारों महाविद्यालय, लाखों अध्यापक और अध्यापिकाएं सफाई के विषय को नहीं पढ़ा सके। अगर उन्होंने इस विषय को पढ़ाया होता तो मोदी जी को यह अभियान नहीं चलाना पड़ता। विषय प्रतिस्थापना करते हुए कथाकार एवं चिंतक रामदेव सिंह ने कहा कि स्वच्छता का सीधा सम्बन्ध स्वर्गिक सुख से है क्योंकि जहां कहीं साफ सुथरी जगह पर हम पहुंचते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कि स्वर्ग जैसा सुख मिल रहा है। उन्होंने सामाजिक चेतना में बदलाव लाने की बात कही। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ. दीनबंध तिवारी ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हुए कहा कि सफाई का सम्बन्ध हमारी सामाजिक व्यवस्था से होती है। उन्होंने स्वयं की जीवन पद्धति को उठाने की बात कही। उन्होंने दो रास्ते बताये कि या तो स्वतः कीजिए या कानून के डर से। राजभाषा अधिकारी दिनेश चन्द्रा ने कहा कि हमें सोच बदलनी होगी और गन्दा करने वाले को गन्दा तथा सफाई करने वाले को उंचा मानना पड़ेगा। पेशे को उंचाई नीचाई से जोड़ना होगा। लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. श्रीमती पुष्पा सिंह ने कहा कि स्वच्छता अत्यन्त आवश्यक है। तन, मन, देश और समाज यदि स्वच्छ हो तो आदर्श स्थिति बन सकती है। लेकिन इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा। साथ ही सिस्टम को भी स्वच्छ रखना होगा। अतिथियों का स्वागत विनय वर्मा, अध्यक्षता राणा प्रताप सिंह, धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक विष्णुकान्त अग्रवाल एवं संचालन डॉ. अनिल यादव ने किया। सह कार्यक्रम संयोजक अनिल गुप्ता उर्फ गुड्डू ने अतिथियों को स्मृति चिह्न प्रदान किया। इस अवसर पर विकास अग्रवाल, सरदार सिप्पू सिंह, देवीचरण कुशवाहा, राकेश रोशन बागी, गोपाल सिंह, अकरम अली, अशोक सोनकर, अजय तिवारी, रामतिलक सोनकर, नारायण सोनकर, सुनील शर्मा, राजाराम यादव, सुधीर पाण्डेय, विशाल तिवारी, अनुराग सिंह, रवि सोनकर, पवन सिंह, राहुल गोंड, शैलेन्द्र प्रताप सिंह, संदीप तिवारी, जितेन्द्र सोनकर, अनीस मिश्रा, विकास सिंह, गोविंद केशरी, मनोज जायसवाल प्रमुख रुप से उपस्थित थे।

डॉ. अनिल यादव

+++

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, हमें लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

माननीय डॉ. उदित राज द्वारा संसद में उठाए गए मुद्दे

शुन्य काल के दैरान (31 जुलाई, 2015)

डॉ. उदित राज (उत्तर- पश्चिम दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वनपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कर रहा हूं। (व्यवधान) सन् 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थ। (व्यवधान) उसके बाद वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बनें।(व्यवधान) फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिषद् मेरे नेतृत्व में बना। (व्यवधान) वाजपेयी जी के साथ तमाम बैठकें हुई, आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से वाजपेयी जी की सरकार ने बहुत महान काम किया और 85 वां संवैधानिक संशोधन पास किया, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है।(व्यवधान) इसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी।(व्यवधान) वह मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है।(व्यवधान) वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में नागराज के नाम से एक केस लड़ा जाता है और पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार हमें मिलता है, अर्थात, 85 वां संवैधानिक संशोधन बैलट किया जाता है। (व्यवधान) फिर 4 जनवरी, 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मना कर दिया। (व्यवधान) उसके बाद वह केस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पदोन्नति में आरक्षण से विसंगतियां पैदा हुई है। (व्यवधान) वर्ष 2012 में यह बिल राज्य सभा में पास हो चुका है लेकिन लोक सभा में पास नहीं हो पाया। (व्यवधान) मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसी सत्र में पदोन्नति में आरक्षण का बिल लाये और पास करे। यही मेरी सरकार से अनुरोध है। लखनऊ हाई कोर्ट की दो जजेज की बेंच थीं। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मना किया, जबकि नागराज केस में पांच जजेज की बेंच थीं। उसके हिसाब से भी पदोन्नति में आरक्षण बरकारार रहना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और अधिकारी समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। उनका डिमोशन हो रहा है, इसे फौरन रोका जाना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में पास हो चुका है मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि लोकसभा में इसी सत्र में पास करके लाखों एससी, एसटी अधिकारियों और कर्मचारियों का रिवर्सल रोका जाए। इनका फरदर प्रमोशन ब्लॉक हुआ है, उसे भी दुरुस्त किया जाए। हरियाण सरकार ने हाल ही में पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ किया है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को धन्यवाद देता हुं कि उन्होंने यह रास्ता साफ किया है, हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए हैं। बिहार, राजस्थान राज्य में कमेटी बनाकर पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है। मेरा कहना है कि इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अतासांकित प्रशन के अन्तर्गत (10 अगस्त, 2015)

डॉ. उदित राज (उत्तर- पश्चिम दिल्ली) : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या सरकार के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों/पीएसयू द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का 20 प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा एमएसएमई के लिए आरक्षित किया गया है।

ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान एमएसएमई और एससी/एसटी/ओबीसी अधिग्रहित एमएसएमई से की गई कुल खरीद का प्रतिशत कितना है।

ग) क्या उक्त नीति रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेदश वाली कंपनियों पर लागू होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और

घ) सरकार द्वारा देश में उक्त नीति के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्रा

क) जी, हां

ख) चालू वित्त वर्ष अर्थात 2015-16 के लिए खरीद संबंधी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजिनक खरीद नीति आदेश 2012 सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएमयू पर लागू है तथा इस नीति में निर्धारित मानकों के अनुसार उनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए पंजीकृत एमएसई से खरीद करना अनिवार्य है।

घ) इस नीति के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है

1. विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) का आयोजन।
2. शिकायत प्रकोष्ठ तथा शिकायतों के निवारण के लिए वेब आधारि प्लेटफार्म का निर्माण।
3. सार्वजनिक खरीद नीति का अनुपालन न होने पर सीपीएमयू के लिए दंड का प्रावधान।
4. विभिन्न सीपीएसयू/रेलवे बोर्ड आदि के साथ अलग-अलग बैठकें करना।

Bill Summary

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2014

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2014 was introduced in the Lok Sabha by the Minister of Social Justice and Empowerment, Mr. Thaawar Chand Gehlot on July 16, 2014.

The Bill replaces the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Ordinance, 2014.

The Bill seeks to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. The Act prohibits the commission of offences against members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SCs and STs) and establishes special courts for the trial of such offences and the rehabilitation of victims.

Actions to be treated as offences: The Act outlines actions (by non SCs and STs) against SCs or STs to be treated as offences. The Bill amends certain existing categories and adds new categories of actions to be treated as offences.

Forcing an SC or ST individual to vote or not vote for a particular candidate in a manner that is against the law is an offence under the Act. The Bill adds that impeding certain activities related to voting will also be considered an offence. Wrongfully occupying land belonging to SCs or STs is an offence under the Act. The Bill defines 'wrongful' in this context, which was not done under the Act.

Assaulting or sexual exploiting an SC or ST woman is an offence under the Act. The Bill adds that: (a) intentionally touching an SC or ST woman in a sexual manner without her consent, or (b) using words, acts or gestures of a sexual nature, or (c) dedicating an SC or ST women as a devadasi to a temple, or any similar practice will also be considered an offence. Consent is defined as a voluntary agreement through verbal ornon-verbal communication.

New offences added under the Bill include: (a) garlanding with footwear, (b) compelling to dispose or carry human or animal carcasses, or do manual scavenging, (c) abusing SCs or STs by caste name in public, (d) attempting to promote feelings of ill-will against SCs or STs or disrespecting any deceased person held in high esteem, and (e) imposing or threatening a social or economic boycott.

Preventing SCs or STs from undertaking the following activities will be considered an offence: (a) using common property resources, (c) entering any place of worship that is open to the public, and (d) entering an education or health institution.

The court shall presume that the accused was aware of the caste or tribal identity of the victim if the accused had personal knowledge of the victim or his family, unless the contrary is proved.

Role of public servants: The Act specifies that a non SC or ST public servant who neglects his duties relating to SCs or STs shall be punishable with imprisonment for a term of six months to one year. The Bill specifies these duties, including: (a) registering a complaint or FIR, (b) reading out information given orally, before taking the signature of the informant and giving a copy of this information to the informant, etc.

Role of courts: Under the Act, a court of Session at the district level is deemed a Special Court to provide speedy trials for offences. A Special Public Prosecutor is appointed to conduct cases in this court.

The Bill substitutes this provision and specifies that an Exclusive Special Court must be established at thedistrict level to try offences under the Bill. In districts with fewer cases, a Special Court may be established to try offences. An adequate number of courts must be established to ensure that cases are disposed of within two months. Appeals of these courts shall lie with the high court, and must be disposed of within three months. A Public Prosecutor and Exclusive Public Prosecutor shall be appointed for every Special Court and Exclusive Special Court respectively.

Rights of victims and witnesses: The Bill adds a chapter on the rights of victims and witness. It shall be the duty of the state to make arrangements for the protection of victims, their dependents and witnesses.

The state government shall specify a scheme to ensure the implementation of rights of victims and witnesses.

The courts established under the Bill may take measures such as: (a) concealing the names of witnesses, (b) taking immediate action in respect of any complaint relating to harassment of a victim, informant or witness, etc. Any such complaint shall be tried separately from the main case and be concluded within two months.

शेष पृष्ठ 1 का

भाषण शुरू हुआ जिसमें प्रमुख रूप से सर्वश्री आर. के. अग्निहोत्री , डी.के. मिश्रा, एस.पी. सिंह, एस.के. यादव, रवी शंकर श्रीवास्तव आदि ने संम्बोधित किया।

इसके बाद विभागीय अधिकारियों के सम्बोधन का शिलशिला शुरू हुआ जिसमें प्रमुख रूप से श्री. एस.एल. मीना साहब डी. जी.एम, क्षेत्रीय प्रबन्धक एन.एन. गुप्ता तथा हमारे इन्जीनियररिंग डिवीजन के इन्चार्च श्री ए. के. गर्ग अधिशासी अभियन्ता जी ने भी सम्बोधित किया और हमारी सेवाकाल में सभी सरकारी एवं समाजिक कार्यो भी भूरि-भूरि प्रशंशा की तथा सभी लोगों ने मेरे विभागीय संगठन ऑल इण्डिया सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारप्रोरेशन अनुसूचित जाति / जनजाति इम्पलाईज फेडरेशन के लखनऊ रीजन के जनरल सेक्रेटरी होने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने तक किए गये कार्यो की प्रशंशा का पुल बांध दिये और डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में गठित अनुसूचित जाति/ जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की उपब्धियों एवं संसदीय इतिहास में किसी सामाजिक/ कर्मचारी संगठन द्वारा केन्द्र सरकार पर दबाव बनाकर तीनों संवैधानिक संशोधन पर

डॉ. उदित राज जी का लखनऊ हवाई अड्डे पर फूल मालाओं से किया स्वागत

आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आज तक कोई राजनैतिक दल अपने दम पर इतना बडा काम नही कर पाया, सभी कर्मचारी नेताओं तथा अधिकारियों में जगजीवन प्रसाद की सराहना करते हुए गर्व महसूस किया कि जगजीवन प्रसाद इतने बड़े कार्य में डॉ. उदित राज जी के बाद दूसरे नम्बर पर बड़े पदाधिकारी थे। जगजीवन प्रसाद जी ने आपने समाज को उनका हक दिलाने के साथ साथ विभाग का भी नाम ऊंचा किया है।

अन्त में जब जगजीवन प्रसाद को बोलने एवं आभार व्यक्त करने का मौका आया तो उन्होंने माईक पकड़कर उपस्थिति जन समूह को नमो बुद्धाय, जयभीम एवं नमस्कार कर अपनी बात शुरू की और कहा कि हमनें डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में छोटी-बड़ी 5 से 10 लाख तक की महारैलियों का संचालन एवं सम्बोधित किया है लेकिन अपनी विदाई पार्टी में कहाँ से शुरू करू यह समझ में नही आ रहा और तुरन्त अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों- कर्मचारियों एवं कर्मचारी संगठन के नेताओं को मालार्पण कर स्वागत करना चाहिता हूं और मैं आपको माला क्यों पहनाना चाहता हूं इसकी वजह मालार्पण के बाद बताऊंगा। कुछ ही क्षणों में हमारे विभागीय संगठन के लखनऊ रीजन के महामंत्री श्री राजाराम जी कई साथियों सहित गुलाब की ढ़ेरों मालाऐं लेकर मेरे पास आ गये। जब हम सभी को माला पहना रहे थे तो कर्याक्रम का संचालन कर रहे हमारे पुराने साथी श्री खुर्शीद रजा साहब किसी बड़े मैदान में हो रहे खेल जैसी कमेन्ट्री कर लोगों को हॅसा-हॅसा कर भावुक एवं खुश कर रहे थे। बहुत लोग हमसे कह रहे थे कि विदाई आपकी है और आप माला हमे पहना रहे हो। इसके बाद जगजीवन प्रसाद पुनः माइक पर आ गये और कहा हमारी विदाई हो रही है जुदाई नही और बताया कि जब हमने परिसंघ का पहला कार्यक्रम लखनऊ के रवीन्द्रालय प्रेक्षगृह में किया था जिसकी अध्यक्षता एवं नेतृत्व डॉ. उदित राज जी ने किया था और मुख्य वक्ताओं में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति /जन जाति आयोग के तत्कालीन चेयरमैन माननीय के. हनुमनथप्पा जी एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जन जाति आयोग के अध्यक्ष आदर्णीय श्री एस.डी. बागला जी थे तथा पूरे भारत के सभी संगठनों के प्रमुख, आई.ए. एस.आई.पी.एस. सहित बहुतो को हम मंच पर कुर्शी नही दे पाये थे, वे बड़े-बड़े अधिकारी पूरे कार्यक्रम के समय मंच के पीछे खड़े रहे क्योंकि सामने भी एक-एक कुर्सी पर दो-दो लोग बैठे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल सूर्यभान जी थे, कार्यक्रम में आई भीड को ध्यान में रखते हुए हमने हाल के बरामदे में चारोतरफ क्लोज सर्किट टी. वी. लगा रखा था, भीड इतनी थी की महामहिम राज्यपाल जी को मंच पर आने में सुरक्षा बलो का सहारा लेना पड़ा था।

उक्त भव्य कार्यक्रम के आयोजन में हमारे सी.डब्लू.सी. के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बिना जाति-भेद के क्योंकि हम तो एस. सी./ एस.टी के आरक्षण की लड़ाई लड रहे थे फिर भी सभी ने इतना चन्दा एवं सहयोग किया जितना हमें पूरे उत्तर प्रदेश से मिला था, इसीलिए हमने अपको माल पहनाकर आप सभी का अभिन्दान किया, लोग खुश होकर बार-बार ताली बजाते और मुस्कराते रहे । हमने बिना नाम लिए सभी वक्ताओं की सराहना की क्योंकि यदि किसी का नाम मुझजे से छुट जाता तो उसे दुख हो सकता था। इस बिदाई कार्यक्रम में हमारे परिवार के भी सभी सदस्य आमंत्रित थे।

अतः हमारे इन्जीनिरिंग विंग के श्री एन. के. श्रीवास्तव जी ने अपने संगठन की ओर से ए माइक्रो ओवन गिफ्ट किया और फेयरवेल पार्टी की और से आदर्णीय क्षेत्रीय प्रबन्धक जी गिफ्ट एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सभी की बार-बार सराहना एवं धन्यवाद करते हुए उपस्थिति सभी साथियों की 2 अगस्त 2015 रविवार को दोपहर भोजन अपने घर 61, अर्जुनगंज को शाम 4 बजे बुलाया जिसमें मुख्य अतिथि डॉ. उदित राज जी परिसंघ चेयरमैन एवं दिल्ली के लोक सभा सदास्य थे।

2 अगस्त 2015 को डॉ. उदित राज जी दोपहर में एयर इण्डिया के विमान से लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुचने पर परिसंघ सहित हमारे विभागीय लोगों ने भी हवाई अड्डा पहुँच जोरदार फुल-मालाओ से लाद दिया और वहाँ से वे सीधे हमारे निवास अर्जुनगंज आये। हमारे घर पर मैझूद हमारे रिस्तेदारों ने सम्मानित समाजसेवियों ने उन्हे पुनः मालो से तथा शाल भेट कर स्वागत किया और उनके साथ फोटो खिचवाये। घर पर आयोजित कार्यक्रम में भी हमारे कई वरिष्ठ साथियों सहित विभागीय अधिकारियों जिनमें सर्वश्री एन.एस. गुप्ताजी क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं एम.एल. मीना साहब, डी.जी. एम. को भी हमारे साथियों ने माला पहनाकर स्वागत किया और शाल भेट किया और डॉ. उदित राज जी के सम्बोधन से पहले कुछ बातें हमारे संगठन के बारे में कहे और सभी उपस्थिति जन समूह का स्वागत करते हुए श्री जगजीवन प्रसाद के उज्जवल भविष्य दीर्घआयु एवं तरक्की के लिए अपनी शुभकामानएं दी।

डॉ. उदित राज जी ने अपने सम्बोधन से पूर्व मंच पर तथागत भगवान बुद्ध एवं डॉ. भीमराव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और जगजीवन प्रसाद जी के स्व. माता-पिता के चित्र पर भी मालार्पण किया। जगजीवन प्रसाद जी में बताया की उनके माता-पिता की मृत्यु एक ही तिथि एवं महीने में हुई थी केवल वर्ष था अन्तर था। माताजी श्रीमती रामकली की मृत्यु 28 अक्टूबर 2013 में हुई और इससे पहले उनके पिता श्री जगपाल की मृत्यु 28 अक्टूबर 2000 को हुई और जिस दिन जगजीवन प्रसादजी श्री परमहंश प्रसाद जी द्वारा कोल इण्डिया लि. सीधी (मध्य प्रदेश) में परिसंघ के कार्यक्रम से लौट रहे थे और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ जन जाति आयोग के अध्यक्ष मा. दिलीप सिंह भुरिया एवं अध्यक्षता डॉ. उदित राज जी की थी।

डॉ. उदित राज जी ने बताया आज जगजीवन प्रसाद जी के आमंत्रण पर पूरे उत्तर प्रदेश से परिसंघ के पदाधिकारी तथा उनके सामाजिक जीवन के लगभग सभी प्रमुख साथी हमको दिखाई दे रहे है उन्होंने तमाम लोगों का नाम भी लिया। उन्होंने कहाँ

डॉ. उदित राज जी को शाल भेट देते हुए अमित राज

लोग नौकरी करते है और सेवानिवृत्त भी होते रहते है और बहुत लोग तो परिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा किये बिना भी दुनिया से विदा ले लेते है। लेकिन जगजीवन प्रसाद जी ने अपनी सरकारी नौकरी भी पूरी कर ली और सभी लड़के-लड़कियों की शादी-विवाह भी कर दिया हैं। हम बता रहे थे कि उन्हे आज तक इनके विभाग के किसी अधिकारी ने पूरे सेवाकाल में एक भी ममो (एक्सपेलेशन) तक नहीं दिया और प्रशंशा के तौर पर आज भी इनके वरिष्ठ अधिकारी हमारी बगल में बैठे है, और इनके सभी प्रमुख साथी कर्मचारी-अधिकार, नेता, प्रशंसक सभी उपस्थिति है। इन्होने विगत 19 जुलाई, 2015 को हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन एवं दलित आरक्षण पर आयोजित चिंतन सिविर में अपने सभी बहू-बेटे परिवार सहित पहुँच कर मेरा सम्मान भी किया और दोपहर का लन्च भी इन्ही की तरफ से था। हमारे लोग जब सेवा निवृति होते हैं तो गया-बनारस, पिण्ड दान, तीर्थ यात्रा तथा ब्रह्मभोज कराते है लेकिन जगजीवन प्रसाद और अन्य लोगो में बहुत बड़ा अन्तर है इन्होने सेवा में रहते हुए समाजिक सेवा की पूरा देश घूमें ओर इनको विभगीय एल.टी.सी. लेने की जरूरत भी नहीं पडी। इनको सरकारी सेवा में रहते हूए सामाजिक कार्यो पर खुश होकर तत्कालीन रेलमंत्री मा. रामविलास पासवान जी ने द्वितीय श्रेणी एस.सी. का पास एक अतिरिक्त साथी सहित दिया और आज इनके छोटे पुत्र श्री विकास दीप एयर इण्डिया में है और आज इनके परिवार के पास हवाई जहाज का भी पास मिला हुआ है। इन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम मेरे नेतृत्व में परिसंघ के आन्दोलन से किया जब जगजीवन प्रसाद जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के पद पर थे तो संविधान में दलित आरक्षण को बचाने के लिए तीन संवैधानिक संशोधन (81 वाँ, 82 वाँ एवं 85 वाँ) हुए थे और आज भी हमारे आन्दोलन में कन्धा से कन्धा मिलाकर चल रहे है। जो लोग समाने बैठे हैं इनके बुलाये पर ही हजारो-हजारो रुपये खर्च कर के आये हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है मुझे विश्वास है कि आज के बाद जगजीवन प्रसाद जी पूरी तरह से सामाजिक सेवा में लगकर एक नया जीवन इनको मिला है आज के बाद इनको पहले से अधिक खुशी एवं अच्छा स्वास्थ रहेगा, आप सभी देखेगें। सभा के अन्त में डॉ. उदित राज ने उपस्थिति जन समूह एवं उनके साथियो से सभी का नाम, पता, मोबाइल नंम्बर एवं इमेल आइ डी लिया और उन्हे सभी के साथ उन्च जल्दी -जल्दी में करना पड़ा जबकी लोग उन्हे और सुनना चाहते थे, लेकिन अपरान्ह 4 बजे उन्हे वी.वीआई.पी गेस्ट हाऊस में पहुँच कर प्रेस वार्ता को सम्बोधित करना था।

प्रेस वार्ता के बाद कई लोगो को परिसंघ की बड़ी जिम्मेदारी दी गई और इसी क्रम में 14 अगस्त को प्रतापगढ़ में जिलेस्तर की, 30 अगस्त को इलाहाबाद में तथा 6 सितम्बर को कानपुर में मण्डलीय सम्मेलन की तिथि की घोषणा भी की गई इन दोनो मण्डलो में मुख्य अतिथि डॉ. उदित राज जी होगें, और पीलीभीत में मुझे जाकर कार्यक्रम को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई और वहाँ भी डॉ. उदित राज जी मुख्य अतिथि होगें। लखनऊ हवाई अड्डे से शाम 6 बजे डॉ. उदित राज जी को जोर दार नारे लगाकर विदा किया गया।

कार्यक्रम में निम्नांकित प्रमुख पदाधिकारी उपस्थिति थे सर्व श्री एन.एन. गुप्ता क्षेत्रीय प्रबन्धक, के.के. वत्स पत्रकार, एस.के. श्रीवास्तव, कालीचरन जी पूर्व विधायक, एम.एल. मीना डी.जी.एम., ए.के.गर्ग. आर.के. अग्निहोत्री, धर्म सिंह, राम सेवक, रवीशंकर श्रीवास्तव, एस.पी. सिंह, राजाराम, एस.एम. द्विवेदी, महेन्द्र विकास बाल्मीकी, सजीवन लाल, चन्द्र कुमार, एन.के. श्रीवास्तव, ए.के. श्रीवास्तव, विजय कुमार, त्रिवेणी सहाय जाटव, वी.डी. भारती, फूलचन्द्र गोपी यादव, सन्त बक्श सिंह गहलोत, के.पी. वर्मा, राजकिशोर, फौजी बौद्ध, राजा बक्श, प्रेम नाथ, सुशील कुमार, अमित राज, राज कुमार सोनकर, आर.के. राज, सोभनाथ सरोज, भानुप्रकाश, गौरी शंकर, दिनेश भारती, डॉ.बसन्त, डॉ. सुमन्त, डॉ. आई. के. सरन, आर.एन. सिंह, अनील कुमार, अभिषेक, सुनील कुमार, संजय राज, के.पी. चौधरी, इंजि.राम रतन, उदय राज प्रधान, रिंक्कू, एच.आर. गौतम, एस.डी. वर्मा, श्रीमती किरन सिंह, राम सजीवन दास, विकास मोगा, बाबूलाल, विन्दादीन, हरिजीवन, राम सजीवन, श्रीमती रीता, उषा, सन्तोखा, प्रेम कुमारी, राज कुमारी, राजाराम आकाश, विकास, विनय, विवेक, विनोद कुमार, आदर्श, राजेश्वरी दीदी, अनुराधा, परमेश्वर दयाल, राम सुमेर, महेन्द्र सरोज, जे.पी. भारती, जगत अवधेश शरण पूर्व एस.पी., राधेश्याम, इंजि. जगदीश प्रसाद, प्रवेश कुमार एस.आइ. नरेश राज इत्यादि उपस्थित थे।

– जगजीवन प्रसाद

Issues Raised by Hon'ble Dr. Udit Raj, MP, in Parliament

Unstarred Question (29 th July, 2015)

Dr. Udit Raj : Will the Minister of HUMAN RESOURECE DELVELOPMENT be pleased to state :

a) The dropout rate of students belonging to the Economically Weaker Section (EWS) during the last three years, State-wise.
b) the step taken by the Government to reduce dropout rates.
C) whether the Government has any plan to link milestones achieved in admission of students of EWS to grants and support received under the Swachh School Abhiyan; and
d) if so, the details thereof?

Answer

MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMNET (Smt. Smriti Zubin Irani)

a) As Per the Unified District Information System for Education (UDISE), the average annual dropout rates of children, including of Economically Weaker Sections (EWS) children, at primary & upper primary level during 2012- 13 are 5.62% & 2.65% , and during 2013-14 these are 4.67% & 3.13% respectively . The annual average dropout rate of EWS children is not capture separately under UDISE.
b) The Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) programmes provide for a multi pronged approach to reduce check dropout rate amongst children, including the Economically Weaker Section (EWS) Student, inter-alia through enhancing access to primary &b upper primary schools, strengthening school infrastructure like school building, additional classrooms, toilets, drinking water facilities etc. improving the pupil teachers ration, strategies for gender positive textbooks, gender sensitization of teachers and education administrators. The mid-day meal programme is implemented in elementary schools, to help retain children in schools. To ensure quality outcomes in government schools, the central Government through ssa has supported State/ UTs on early grade reading, writing & comprehension and early mathematics programmes throught a sub-programme namely padhe bharat Badhe Bharat and at upper primary level sipport for mathematics and Science teaching learning. The Ministry has also launched Rashtriya Avishkar abhiyan programme as sub-component of SSA and RMSA to motivate and engage children of the age group of from 6 to 18 years in Sciens, Mathematics and technology through observation, experimentation inference drawing, model building etc. both through inside and outside classroom activities and Processes.
C) No, Madam.
D) Does not arise.

Unstarred Question (29 th July, 2015)

Dr. Udit Raj : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:-

(a) the details of the funds allocated and number of beneficiaries in different States including Haryana under the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme during each of the last two years, State /UT-wise.
(b) whether there is a mechanism to ensure that the pension is reaching to the intended beneficiaries
(c) whether the Government has identified additional beneficiaries under the amended eligibility criteria of the said scheme, if so, the details thereof.
(d) the achievements made in this regard, State / UT-wise; and
(e) whether the Government has any fresh proposal to increase the pension amount to the beneficiaries under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI BIRENDER SINGH)

a): Schemes under NSAP have been converted into a Centrally Sponsored Scheme (CSS) from the financial year 2014-15 and funds are now released Scheme- wise. However, prior to 2014-15 schemes under NSAP were under State Plan and funds for NSAP were allocated by Planning Commission and are released as Additional Central Assistance (ACA) to the States by the Ministry of Finance and by the Ministry of Home Affairs to Union Territories in a combined allocation for all the schemes under NSAP. Details of the funds allocated and the number of beneficiaries in different States including Haryana under the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme during each of the last two year, State /UT-wise is at Annexure-I.

b): In order to increase the transparency and accountability in the implementation of schemes under NSAP, a software namely NSAP-MIS had been developed which captures all the essential processes and includes modules on identification, disbursement of pension, release of funds, verification, sanction of pension, ground for refusal etc. Sates have also to give monthly physical and financial progress of the schemes of NSAP in the Monthly Progress Report(MPR) . Direct Benefit Transfer (DBT) has also been introduced in the pension scheme of NSAP so that the pension may transfer in the accounts of beneficiaries regularly. Post facto verification with community participation is also done through social audit.

c): & (d): States / UTs have already been communicated about the estimated number of beneficiaries under the schemes of NSAP. States / UTs have also been communicated that they may add new names and delete the ineligible names from the BPL list 2002 on a continuous basis during the validity period of the BPL list 2002 for providing benefits to the eligible beneficiaries under different schemes of NSAP. The addition /deletion from the BPL List should be done following a transparent and participatory process which should also include an appellate system.

e): At present there is no proposal to increase the pension amount under the schemes of NSAP.

Unstarred Question (30th July, 2015)

Dr. Udit Raj : Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYSbe pleased to state:-

(a) whether the Government has revised the fee for All India Tourist Permit Buses;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether the number of tourist buses registered in Tamil Nadu under All India Tourist Permit that have decreased due to revision of fee; and
(d) if so, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI PON. RADHAKRISHNAN)

(a) No, Madam.
(b) to (d) Does not arise in view of (a) above.

Unstarred Question (03 rd August, 2015)

Dr. Udit Raj : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:-

(a) the details of major and minor catering contracts at railway stations awarded to SCs and STs as per the reservation policy of the Railways, zone-wise and division-wise;
(b) the details of the criteria/norms being followed by the Railways for allotment of catering contracts under the reservation policy; and
(c) whether the Railways are considering to allow SCs/STs to form cooperatives to participate in tendering process so as to enable them to meet the eligibility criteria for allotment of such contracts and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA)

(a) to (c): In the new Catering Policy, 2010 in continuation of previous Catering Policies, the provision of 25% reservation in allotment of minor static unit at A, B & C categories and 49.5% reservation in allotment of minor static unit at D, E, & F categories of stations has been made with a view to protect interest of socially backward and economically weaker sections of the people. Out of the total 25% reservation at A, B and C category stations, a quota of 6% for Scheduled Castes (SCs) and 4% for Scheduled Tribes (STs) has been reserved for allotment of minor catering units. Similarly, out of the total reservation of 49.5% at D, E & F category of stations, a quota of 12% and 8% for SCs and STs respectively has been reserved. The details of minor catering contracts at railway stations awarded to SCs and STs as per the reservation policy of the Railways are annexed.

Major units are awarded through open, competitive, two packet tender system having stringent eligibility criteria so as to provide professional good quality catering services to the travelling public. Applicants from reserved category can also participate in the bidding system of major units subject to fulfilment of the eligibility criteria, since, there is no provision of reservation in award of major units.

Unstarred Question (04 th August, 2015)

Dr. Udit Raj : Will the Minister of HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES be pleased to state:-

(a) the details of funds earmarked and utilised by the Central Public Sector Undertakings (CPSUs) including Maharatna, Navratna and Miniratna under Corporate Social Responsibility (CSR) during each of the last three years and the current year;
(b) the funds allocated by each CPSUs to various channelising agencies viz. NGOs/Trusts/Societies and the percentage of fund directly spent during the said period, CPSU-wise;
(c) whether the Government monitors the utilisation of funds under CSR and if so, the details thereof; and
(d) the policy of the Government for utilisation of CSR funds including on developmental work by these CPSUs and in the backward areas of the country?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE FOR HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA)

(a)to (d): The policy of the Government for implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by companies including Central Public Sector Enterprises (CPSEs) is provided in Section 135 of Companies Act, 2013 which states that all companies whose net worth is Rs. 500 crore or more, or turnover is Rs. 1000 crore or more or has a net profit of Rs. 5 crore or more are required to spend 2% of their average net profits of three immediately preceding financial years for activities specified in Schedule-VII of the Act. These provisions are to be complied with by all CPSEs including Maharatna, Navratna and Miniratna CPSEs with effect from 1.04.2014.

The responsibility of implementation lies with the respective Board of Directors of the CPSEs and the details for the first year for implementation of the provisions of Section 135 i.e. 2014-15 are not maintained centrally by Department of Public Enterprises.

Unstarred Question (05 th August, 2015)

Dr. Udit Raj : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:-

(a) Whether the Government had allotted land to the Scheduled Castes, widows, Other Backward Classes, military personnel and poor people under 20-Point Programme in the year 1970 and 1976; and

(b) If so, the details thereof and the action taken/being taken by the Government for conferment of bhumidhari rights to these people?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI BABUL SUPRIYO)

(a) & (b) : Yes, Madam. The Government of NCT of Delhi has allotted land under 20-Point Programme in the year 1970 and 1976 and has informed that reliable records in support of the Bhumidhari claims are not available.

Unstarred Question (07 th August, 2015)

Dr. Udit Raj : Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:-

(a) whether there has been substantial growth in the investment made by Canada in our country during the past few years and if so, the details thereof.

(b) whether the investors from Canada have shown interest to invest in the country during the recent visit of Prime Minister to Canada and if so, the details thereof.

(c) the areas/sectors identified for further cooperation and agreements/MoUs signed to boost trade and investment during the said visit. and

(d) the efforts made by the Government to bring this investment into the country at the earliest?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN)

(a): The total amount of FDI equity inflow received from Canada since April, 2000 to May, 2015 is US$ 549.37 million. Year-wise FDI inflow received from Canada during the last 5 years are as under :-

<pre>
Year FDI inflow(in US $ million)
2010-11 33.66
2011-12 39.78
2012-13 42.04
2013-14 11.32
2014-15 91.10
2015-16 (Upto May, 2015) 21.28 </pre>

(b): The Prime Minister met CEOs of Pension Funds of Canada and investors during his visit to Canada and showcased how Canada's capital and technology can combine with economic opportunities in India.

(c): The areas that have been identified for further cooperation are trade and investment, civil nuclear cooperation, energy, education and skills development, agriculture, defence and security, science, technology, innovation and space, culture, people-to-people ties, and regional and global issues. The Prime Ministers of Canada and India reaffirmed the need to elevate two-way trade and investment linkages to their full potential during the visit.

(d): Significant changes have been made in the policy and procedures, to ensure that India remains increasingly attractive and investor-friendly.

Unstarred Question (10 th August, 2015)

Dr. Udit Raj : Will the Minister of MICRO,SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:-

(a) whether the Government has a Public Procurement Policy for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) under which a minimum share of 20 per cent of the total purchases made by Central Ministries/Departments/PSUs has been reserved for MSMEs;

(b) if so, the details thereof including the percentage of total procurements made from the MSMEs and SC/ST/OBC owned MSMEs during the current year;

(c) whether the same policy is applicable to the companies having foreign direct investment in retail sector and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(d) the steps taken by the Government to enforce proper implementation of the said policy in the country?

ANSWER

MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI KALRAJ MISHRA)

(a) Yes, Madam.

(b) The procurement details for the current financial year i.e. 2015-16 is not available.

(c) The Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order 2012, as implemented by the Ministry of MSME is applicable to all Central Ministries/ Departments/CPSUs and they are mandated to procure the requirements as per the norms laid down in the Policy from registered MSEs.

(d) The steps taken by the Government to enforce proper implementation of Policy include:-

i. Organizing Vendor Development Programmes (VDP).
ii. Grievance Cell and created web enable platform for redressal of grievances.
iii. Penalty Provision for CPSUs for non compliance of Public Procurement Policy.
iv. One to one meetings with different CPSUs/Railway Board etc.

Unstarred Question (10 th August, 2015)

Dr. Udit Raj : Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:-

(a) whether there are reserved posts for promotion from Manager to Senior Manager in the Airports Authority of India (AAI);
(b) if so, the details thereof;
(c) whether AAI has removed these reserved posts from promotion; and
(d) if so, the details thereof along with the reasons therefor?

ANSWER

Minister of State in the Ministry of CIVIL AVIATION (Dr Mahesh Sharma)

(a) & (b) : No Madam. Reservation in promotion from Manager to Senior Manager (which is within Group "A") is not applicable in terms of the Government of India instructions, according to which reservation in promotion by selection is applicable upto the lowest rung of Group "A" i.e. Manager (E-3).
(c) & (d) : Do not arise.

Unstarred Question (11 th August, 2015)

Dr. Udit Raj : Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-

(a) whether the Ministry has any proposal to request the Ministry of Finance for amending GFR 142 and 144 to give preference to SC contractors/suppliers in all kinds of Government supplies/ tenders/contracts etc.; and
(b) if so, the details thereof and status thereon?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI VIJAY SAMPLA)

(a) and (b) The Ministry does not have any proposal to request the Ministry of Finance for amending GFR 142 & 144.

However, the new Public Procurement Policy of the Ministry of Small Micro & Medium Enterprises (MSME) notified on 23.3.2012, provides for the sub target of 20% for procurement from SC/ST entrepreneurs of the total 20% procurement from MSEs in phases. From1st April, 2015, overall procurement goal of minimum 20% from MSMEs owned by SC/ST entrepreneurs is to made mandatory.

Dr. Udit Raj raised this issue under Rule 377 in the Lok Sabha on 12th August 2015

Almost all Government departments including those under the Union Government of India and those under state Governments have SC/ST welfare associations. Purpose of these welfare associations is to air the grievances of SC/ST employees, but very often they are denied access to authorities. Personal meetings with the authorities and necessary facilities like office accommodation and related paraphernalia are also denied to SC/ST welfare associations as well. At many places, the authorities are pressurized by general category unions not to recognize SC/ST unions and resolve their problems. Even if the SC/ST associations are not provided the facilities and power at par with general unions, their grievances should be entertained and meetings should be granted for them. Often the pretext that there is a dispute, all groups is not entertained by the concerned management. This is nothing except prejudice towards SC/ST associations and there is no harm in authorities granting them time and resolving their grievances. After all, strength of SC/ST employees is around 25% of the total workforce, and neglecting their welfare associations means either disappointing them or neutralizing their opinion, which has an overall bearing on the functioning of the Government. I request that SC/ST welfare associations be should be allowed to hold meetings with the management and present their grievances to them.

49% of Haryana dalit kids malnourished

29 Julty, 2015 Chandigarh: As much as 49% of the children from families falling in Scheduled Caste category in Haryana are malnourished, claimed a report by an NGO working for dalits.National Confederation of Dalit Organizations (NACDOR) presented the report, prepared under.

National Campaign on Nutrition for Dignity (NCND), during a consultation seminar organized in Chandigarh.

"This study is of national importance to build new strategies and change our approach towards the betterment of dalits and other groups that have been marginalized for centuries.Now nutrition needs to be given the utmost priority," said NACDOR chairman Ashok Bharti. A delegation of NACDOR team also met trans port and housing minister Krishan Lal Panwar to take up this issue with Haryana government. But the state additional chief secretary (women and child development) Avtar Singh expressed inability to comment on the matter saying he was yet to see the report.

NACDOR is an apex body of more than 2,100 dalit outfits working in 24 states of India. With the support from Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), it started NCND to ensure nutritious diet security to dalits and adivasis (tribals).

The campaign is gaining momentum in 14 states as the national-level group has conducted grassroot social audits and created report cards on the status of nutrition among dalits and adivasis, a social audit manual of nutrition schemes and national status report on nutritional status.

- Time of India

✦✦✦

protect their rights. He explained at length how media and whatsapp can be utilized for the Confederation. If all of us start using it, we may get any information in seconds, at no cost. Whatsapp no. of Confederation is 9999504477, on which you may also send your complaints and reports. He informed some of our Pradesh Presidents have started using whatsapp and social media. The day all of us would start doing it, it will help launch a nation-wide campaign. On this occasion he gave the slogan of 'Dalit Vikas – Rashtra Vikas'. He called upon the participants to write this slogan on the walls, on their vehicles and at other places. He further informed that recently the Government has constituted National Judicial Commission. Some people are spreading the rumour that it would increase political interference. It would not give a chance to Dalits and women to become judges. Most injustice is done to us by the judiciary because Swarnas dominate the system. In the Collegium only such people become judges. All Confederation colleagues may write to the President, the Prime Minister and the Chief Justice of India that Dalits have been put to loss by this system. We, therefore, support the NIAC system.

Dr. Udit Raj informed that in the first week of August membership appraisal will be initiated and he would call some people to Delhi. He said that he would himself go to faraway places. He said appraisal would also be done through audio conferencing. It would make it easy if Pradesh Presidents send us mobile numbers and e-mail addresses of active people. Through this system 480 people may interact with me at the same time. He said many leaders should be ready to lead the campaign at the national level. He also informed that everybody has tremendous mind power. Any person uses only 5 to 10% of his mind power. He said people think something else and do something else. If we make a little effort then it would not be difficult for us to unite people with our campaign. He lamented most of our Pradesh Presidents could not constitute District Units. Their leadership would not become effective till they accomplish this task.

Dr. Udit Raj Felicitated

National General Secretary Shri Brahm Prakash led the dais. He retorted those who criticize Dr. Udit Raj, preserve his articles and speeches in their homes and libraries. It goes to prove the intelligence and importance for the Samaj. Shri Ravinder, General Secretary, Delhi Pradesh Unit, said people today criticize Dr. Udit Raj that he has joined the BJP. He said he would like to take the audience a little backwards when the Association was formed. Then the patrons of the Association used to be Members of Parliament of the ruling party. Through them we used to highlight the grievances of our Association. Today the head of our Association is himself a Member of Parliament, which is a matter of pride for all of us. Today we have reached at a respectable place. Had there been no reservation, we could have never reached this place. Shri Ravinder Singh further said that Delhi Unit is receiving the cooperation of Dr. Nahar Singh, President; Shri Karam Singh Karma, Vice President; Shri Dhara Singh; Shri Satya Narayan; Shri R.S. Hans; Shri Bhanu Punia, Shri Yogesh Anand; Shri Balbir Singh – all Secretaries; Shri Jai Ram Singh, Treasurer; Shri Ashok Ahlawat, et al. Delhi Unit handed over an amount of Rs. 1,05,000/- (Rupees one lakh five thousand only) received through donations. He appealed to all colleagues of the Confederation to canvass membership by making home to home visits.

President, Uttar Pradesh Unit of the Confederation, Shri Jagjivan Prasad, informed that he could reconstitute only four-five Zones in his State which has seventy districts. It would take about two months time to visit all the districts. He said that he would first visit all the districts and make office-bearers and assign them membership duties. He said non-Government employees are also being made members. He appealed to members from Uttar Pradesh to come forward and remain in the country. He informed that Uttar Pradesh Unit has now become active and we would soon see its results. He informed when the Confederation was started, they used to attend public functions even with or without invitations and discussed about the Confederation. We will have to switch over to that mode once again at the District and State levels. We have to devise methods for becoming active.

General Secretary Shri Dharam Singh said they are finding Hon'ble Dr. Udit Raj ji doing selfless service for the Dalits after Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar. Today in a period of one year we have raised our voice thirty times in Parliament. No other Member of Parliament has ever raised questions in Parliament on Dalit issues so many times in a year. He informed that in the month of December 2015 a historic Mammoth Rally will be organized in Uttar Pradesh.

Office bearers of Confederation

Shri Param Hans Prasad, President, Madhya Pradesh Unit of the Confederation, said that the audience has listened to the grievances of SC/STs and we will have to strengthen the hands of Dr. Udit Raj ji to seek redressal and till we do that we will not be able to ensure reservation in private sector. On the day the Government will come to know that members of SC/ST communities have united under the banner of All India Confederation, and are bent upon their demands, and if they do not concede to their demands, they will be put in imbroglio in making the next Government.

Coordinator of Andhra Pradesh Unit Dr. Shyam Prasad informed the audience about activities in the State and informed that to mobilize membership; they have constituted teams at all the District levels in their State and have made membership of 6,000 and target to achieve one lakh membership. On achieving this target, there will be an Oath-taking Ceremony in the State.

President of the Haryana Unit of the Confederation, Shri Satya Prakash Jrawta said that he has undertaken tour of eight districts of the State and has raised a membership of 1,250. He said it is due to the campaign launched by the Confederation that the Government of Haryana is giving reservation in promotions. He thanked Maha Singh Bhurania, Satyawan Bhatia and others for their cooperation in this field.

Shri Tarsem Singh from Punjab said that he has raised membership of 3,500 out of the 5,000 forms he had received. He also informed that some of the members could not come to the Conference due to certain familial compulsions. He deposited some forms and Rs. 20,000/- and assured that soon he would deposit all the 3,500 in the National HQ of the Confederation.

Giving details of membership in Oreya District of Uttar Pradesh, Shri Neeraj Chak said that around 350 members were made in Oreya and Itawa District and deposited Rs. 30,000.

Shri Khem Chander from CBSC said that 75 members have been made in CBSC and deposited Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) from his person.

Maharashtra Pradesh President Siddharth Bhojne said that they have visited 30 out of 34 districts of Maharashtra and have made one thousand members. He assured that he would complete 5,000 membership in one week.

Pradesh President of Telangana, Shri Maheshwar Raj said that Meditation Camp and the Conference aimed at membership mobilization has been very important. He informed that they have made 3,000 members and soon they would achieve the target of 50,000 members.

Bihar State President, Shri Madan Ram said that they have made 1,300 members out of the 2,200 forms and their membership campaign continues. Soon they will add members in thousands.

Shri Parmendra, National Adviser to the All India Confederation of SC/ST Organizations informed that the National Chairman, Dr. Udit Raj ji has assigned him organizational work of his North-West Delhi Constituency. He had received 1,500 forms for this Constituency out which he has made 1,100 members. He asked if ten crore members can be made for BJP, cannot we make ten thousand members of the Confederation. We should have rather been given a target of one or two crore. He informed that those SC/ST students who wish to do B.Tech or Polytechnic, free of cost, may contact him at mobile number 8826180767.

Shri Mandal from West Bengal informed that they have 300 members and their membership drive still continues.

Shri Heera Lal from Uttarakhand informed that they have made around 200 members. Cruel rains slackened their membership drive. They would soon give details of their membership should the weather shows some mercy.

In the end Shri Jagjivan Prasad offered the audience lunch on the eve of his forthcoming retirement from service on 31st July, 2015.

- C.L. Maurya

+++

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 18 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 August, 2015

DAY Long Conference

Under the stewardship of Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of ST/ST Organizations, one-day National Conference and Dalit Brain Storming Camp were held at Speaker Hall, Constitution Club, New Delhi. Respected Shri Udit Raj ji arrived at the venue around 11 in the morning amidst tumultuous clapping. Representatives from all over the country welcomed him along with their team who participated in the programmes in large numbers.

Dr. Udit Raj Addrering in rally

Addressing the gathering Dr. Udit Raj said when the programme was for two days all the office-bearers coming across the country got an opportunity to speak. But due to the restriction of one day, it may not be possible that all office-bearers place their views. He said speeches may not do any constructive work. It is wrong to believe that Governments get afraid of our education and speeches. He said that his 18 years experience tells him that our Confederation is the real force behind all of us. The question then arises as to how we may get our rights. How much injustice and atrocities are committed against us? Where we stand? We do lack in cadre building. He also took assessment of the membership in the country from representatives from all over the country. He informed that there is a draw system for raising issues in Parliament. Despite that he raised the issue of reservation and Dalits in Parliament as far as possible. He further informed that he addressed the Parliament 35 times out of which he spoke on Dalit issues thirty times. He wished many more from amongst us may reach Parliament so that more issues could be sorted out. He said it was not his ambition to reach Lok Sabha. His main objective was upliftment of the Samaj. He reminded that in 2000 Dalits assembled in large numbers but then people united out of self-interest. Today we have people with missionary zeal. He informed Confederation work is going on today with unprecedented speed. But we could not achieve the target. On his joining BJP some people started spreading rumours that it would adversely affect the Confederation work but that doubt is removed by now. He informed that it was Uttar Pradesh which put a blanket ban on the reservation policy and that very State is asking now what Dr. Udit Raj is doing? The Confederation, which won the battle for reservation, is being questioned. People, who harmed the reservation, are being protected. He informed that Let. Atal Behari Vajpayee Government passed 85th Constitutional Amendment. The Confederation challenged this Amendment in the Supreme Court and won. This case is known as Nagraj versus Others. This case was referred to the Lucknow bench of Allahabad High Court . Supreme Court wanted to know if the criteria for reservation stipulated by it are being fulfilled by the Uttar Pradesh Government or now. Smt. Mayawati was the then Chief Minister of Uttar Pradesh. She could reply to the Hon'ble Court and reservation would have been saved. Instead she filed a case in the Supreme Court and the reservation for promotion was banned. Although two-judge-bench cannot overrule the decision of five-judge-bench yet it is being done. Had Dalit Samaj put pressure on Mayawati ji, she would not have done so. He said today most of the Dalit organizations are playing the caste card. All India Confederation is the only conglomeration which does not give any credence to any caste card. Its office-bearers are elected on the basis of their hard work. He said anybody can verify this fact by looking at the organizational set up of the Confederation. He said whatever rights we get, we get them through politicians. A general atmosphere prevails today that politicians are the corrupt and the general public is above board. He said Dalit Samaj also propagates that people who fought for the upliftment of the Samaj have vanished and today there is nobody to take care of the Samaj. He said when parties led by Swarnas give them any target they surpass it but when the target is given by the Confederation, these people find lame excuses.

Dr. Udit Raj Best Wishes Shri Jagjiwan Prasad & his family

He further informed the question is now being asked why Dr. Udit Raj is begging BJP. Rather he should protect rights of the Dalits. He asked if it is practically possible. – Any Member of Parliament has his or her own limitations. You all are educated and you know what an MP can do. Until our Confederation is strong, our Samaj will not cooperate with us. That I alone cannot

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar